

अच्छा वक्त
उसी का होता
है जो किसी का
बुरा नहीं सोचते।
- अज्ञात



छात्रों की बेचैनी

पहले जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और अब जेएनयू में हुई हिंसक घटनाओं के ब्यौरे बताते हैं कि इनके ज्यादा बड़े सूत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर हैं।

उमा जोशी।

जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा को किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई मारपीट की तरह नहीं देखा जा सकता, हालांकि इसकी ऐसी ही शकल देश के सामने पेश की जा रही है। विश्वविद्यालयों से छात्रों की बेचैनी और संगठनों के हिंसक टकराव की खबरें पिछले कुछ सालों से लगातार आ रही हैं, लेकिन पिछले पंद्रह-बीस दिनों में हुई ऐसी घटनाओं को अलग रोशनी में ही देखा जा सकता है। पहले जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और अब जेएनयू में हुई हिंसक घटनाओं के ब्यौरे बताते हैं कि इनके ज्यादा बड़े सूत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर हैं। इन घटनाओं में मुख्य भूमिका सरकारी तंत्र और उसके नजदीक रहकर उत्पात मचाने वाले बाहरी तत्वों की बताई जा रही है।

शासन के विवादित फैसलों से समाज में फैले असंतोष और उसे दबाने की कोशिशों का कुछ नाता भी इन घटनाओं से दिखता है, हालांकि इस बारे में ठोस जानकारी तटस्थ जांच से ही सामने आ सकती है। बीते रविवार बाहरी नकाबपोशों का जेएनयू में घुस आना एक ऐसा तथ्य है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। देश की राजधानी में स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था वाले एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में लाठी, डंडे, रॉड लिये गुंडे अचानक घुस आए और वहां घंटों तांडव मचाकर सुरक्षित निकल जाएं, यह बात आसानी से गले नहीं उतरती। जेएनयू प्रशासन से ही नहीं, दिल्ली के पुलिस तंत्र से भी कुछेक असहज कर देने वाले सवाल के जवाब अपेक्षित हैं। यह तो ठीक है कि पुलिस ने जामिया

वाली गलती नहीं दोहराई और बाहरी हमले की सूचना होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन के बुलावे का इंतजार किया। लेकिन उसके कैंपस में पहुंचने के बावजूद एक भी नकाबपोश गुंडा पकड़ा नहीं जा सका, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ हमले पुलिस की मौजूदगी में भी हुए— यह बात दिल्ली पुलिस की छवि से मेल नहीं खाती। यूनिवर्सिटी के सभी गेटों पर पहरे बिठाकर गुंडों को बाहर जाने से रोकना भी क्या इतना कठिन काम था? पुलिस कह रही है कि उनमें से पांच-छह की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तो वह यह बताए कि अपवाद स्वरूप भी उनमें से कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे

मामले की जांच के लिए एक कमेटी बिठा दी गई है, लेकिन खुद पुलिस की ढिलाई के पीछे किसका हाथ था, यह जानकारी न्यायिक जांच में ही निकल कर आ सकती है। अच्छा होगा कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार इसे हल्के में न ले।

देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में सौ-पचास नकाबपोश अगर मार-काट मचाकर बेदाग निकल जाते हैं, तो ऐसा किसी भी हाई सिक्योरिटी कैंपस में हो सकता है— कोई मंत्रालय, कोई मीडिया संस्थान, कोई ऐतिहासिक-सांस्कृतिक धरोहर। सरकार अगर राजधानी में अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखना चाहती है, तमाम तरह के षड्यंत्र सिद्धांतों को हवा नहीं देना चाहती तो उसे न्यायिक जांच का आदेश देकर सचाई सामने आ जाने देना चाहिए।

प्रेम क्या है

योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी।

प्रेम परमात्मा है, तो मैं भक्त की भाषा बोल रहा हूँ... तुम्हें जो रुच जाए, तुम्हें जो ठीक पड़ जाए...

धर्म-दर्शन



.. अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि प्रेम में तुम सरलता से पिघल पाते हो, तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है सुगमता से, तुम्हारा दिल डोलने लगता है, तुम नाचने लगते हो कृतुम्हारा मनमयूर नाचने लगता, तुम्हारे भीतर एक छंद पैदा होता है। एक स्फुरण होती है, रोआकू रोआ किसी रोमांच से पुलकित हो जाता है, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम का भाव रोमांच लाता हो, तो पहचान लेना कि तुम्हारे लिए भक्ति ही द्वार है. 'सेवा क्या है।' 'सेवा कर्म काटने का माध्यम है।' 'सेवा आपके मन को विनम्र' बनाती है तन को चुस्त रखती है।' 'मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है।' 'सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है।' 'निस्वार्थ सेवा,' 'जीवन में सुख शांति लाने का' 'सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

संपादकीय

न्यूनतम आय की गारंटी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान कर चुनाव को राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे से हटाकर सामाजिक-आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी बीजेपी के अलावा नीति आयोग ने भी इस पर सवाल उठाए थे लेकिन चुनाव पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस योजना को बीजेपी सरकार द्वारा किसानों को सालाना 6000 रुपए देने की घोषणा का जवाब माना जा रहा था।

सियासी हलके में इस पर खलबली तो थी ही, अर्थशास्त्री भी मंथन करने में जुट गए हैं। सबके सामने यही सवाल है कि इस योजना के लिए संसाधन कहां से लाए जाएंगे? लेकिन यह सच्चाई है कि भारत का सुपर रिच तबका अभी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बहुत कम टैक्स देता है। तमाम सरकारें टैक्स के नाम पर नौकरीपेशा मध्यवर्ग को ही निचोड़ती आई हैं। कांग्रेस अगर अपनी इस योजना के लिए देश के एक प्रतिशत सुपर अमीरों पर टैक्स बढ़ाती है तो यह एक नई शुरुआत होगी।

भारत जैसे देश में, जहां आर्थिक असमानता बढ़ने की रफतार भीषण है, गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी करना बेहद जरूरी है। सामाजिक असंतोष को कम करने का यह एक बेहतर जरिया हो सकता है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस को इसका जरा सा भी राजनीतिक लाभ नहीं मिला।

इसके पीछे इमरान सरकार की सोच चाहे जो भी रही हो, इलाके के आम लोग इस बात को पोजिटिव ढंग से लें, यह सुनिश्चित करने की कोई ठोस कोशिश वहां शायद ही हो पाई है।

ननकाना साहिब की घेरेबंदी

अमर वर्मा।

पाकिस्तान में बीते शुक्रवार को सिखों के पवित्र तीर्थ ननकाना साहिब की घेरेबंदी और पथराव की घटना ने न केवल पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरी दुनिया के सिखों का ध्यान खींचा। पथराव के पीछे एक सिख लड़की के कथित अपहरण और जबरन धर्मांतरण के बाद शादी का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद संबंधित परिवार ने ननकाना साहिब पर धरना दिया। भीड़ द्वारा पथराव की घटना वहां इसी दौरान हुई। इस प्रकरण ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को एक बार फिर रेखांकित किया है। पाकिस्तान सरकार अन्य देशों, खासकर भारत में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को लेकर जितनी चिंता आजकल दिखा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह घटना और महत्वपूर्ण हो जाती है।

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों की स्थिति पर चिंता जताते हुए एक विडियो टवीट किया, जो बांग्लादेश का था। बहरहाल, ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी करीब 80,000 है। जिला मुख्यालय भी यह 2005 में बना है। संख्या



और आर्थिक व सामाजिक हैसियत के लिहाज से सिख पाकिस्तान में हाशिये पर हैं। जाहिर है, सिखों के इस धर्मस्थान की यहां के ज्यादातर स्थानीय निवासियों की नजर में कोई खास अहमियत नहीं है। ऐसे में पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वहां आने की इजाजत देकर अचानक इस शहर का दर्जा काफी ऊंचा कर दिया।

इसके पीछे इमरान सरकार की सोच चाहे जो भी रही हो, इलाके के आम लोग इस बात को पोजिटिव ढंग से लें, यह सुनिश्चित करने की

कोई ठोस कोशिश वहां शायद ही हो पाई है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह संभावना कम है कि किसी भी क्षेत्र की ज्यादातर आबादी किसी अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक स्थिति में अचानक आई बेहदरी को सहजता से ले सकेगी। ननकाना साहिब जैसे दूर-दराज इलाके का तो कहना ही क्या। ऐसे में बहुसंख्यक प्रतिक्रिया का इलाज क्या है, सिवाय इसके कि वहां लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु बनाया जाए, उन्हें धार्मिक कट्टरता के जाल से मुक्त करने का प्रयास किया जाए।

जाहिर है, यह काम पाकिस्तान की सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों को ही करना है। वहां के रोशन ख्याल लोग इसके लिए आगे आ सकते हैं और एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष पड़ोसी देश के रूप में हम उन्हें अपना वैचारिक और नैतिक समर्थन दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। जो लोग इस संदर्भ में नागरिकता संशोधन कानून का हवाला दे रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे पीड़ित मजबूरी में इधर आए वह अलग बात है, लेकिन अगर वे हमारे बुलाने पर भारत आते हैं तो उन्हें इज्जत की जिंदगी हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे सभी समुदायों को अपनी लड़ाई अपनी जमीन पर लड़नी होती है और बहुसंख्यकों के साथ मिलकर लड़नी होती है।

सूटोफु नववाला- 5219					सूटोफु नववाला- 5218 का खेल									
4	7	1		3	9	2	7	4	8	6	5	3	1	
3	5	4		1	5	1	6	3	2	9	4	8	7	
2				8	3	4	8	7	1	5	9	6	2	
4	3				8	3	4	9	5	1	2	7	6	
8				1	7	6	5	8	4	2	3	1	9	
				8	6	1	9	2	6	3	7	8	5	4
				8	6	6	7	3	2	9	8	1	4	5
				3	6	2	8	1	5	7	4	6	9	3
				4	9	4	5	9	1	6	3	7	2	8

अपना ब्लॉग क्यों नहीं चमक पाई बाकी लीग

रौशन कुमार झा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) शुरू होने के बाद देश में लीग आधारित खेलों का जैसे एक दौर चल पड़ा। इसकी सफलता से प्रभावित होकर दूसरे खेलों में भी लीग की शुरुआत होने लगी। जिस क्रिकेट को दूसरे खेल के खिलाड़ी यह कहकर कोसते रहते थे कि इसकी वजह से हमें पहचान नहीं मिल पा रही, उसी ने आईपीएल को यह कहकर धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से हमें भी अब दौलत और शोहरत मिलने लगी है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आईपीएल तो दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर बढ़ता चला जा रहा है, बाकी खेलों की लीग फीकी पड़ती जा रही हैं। हॉकी की बात करें तो आईपीएल से पहले ही 2005 में प्रीमियर हॉकी लीग शुरू हो चुका था, मगर यह 2008 तक ही चल सका। 2013 में दोबारा हॉकी इंडिया लीग नाम से इसकी शुरुआत पहले से बेहतर तरीके से हुई। आईपीएल की तरह ही इस लीग में भी दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे जिससे भारतीय खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा था। लेकिन 2017 आते-आते इसने भी दम तोड़ दिया। बिना कोई वजह बताए 2018 में इसे स्थगित कर दिया गया।

